DAINIK BHASKER N.D 27/09/2018

19 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा, इंपोर्टेड एसी, फ्रिज, जूते-चप्पल, ज्वैलरी जैसी चीजें होंगी महंगी

रुपए को कमजोर होने से बचाने के लिए सरकार ने उठाया कदम

बढ़ा हुआ शुल्क आज से ही लागू, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया

एजेंसी | नई दिल्ली

सरकार ने 19 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इनमें एसी, फ्रिज और वाशिंग मशीन से लेकर ज्वैलरी और जूते-चप्पल तक शामिल हैं। इससे ये इंपोर्टेड वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। बढ़ा हुआ शुल्क गुरुवार से लागू होगा। इस का मकसद आयात बिल कम करना है, ताकि रुपए को और कमजोर होने से बचाया जा सके। जिन वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया गया है, 2017-18 में उनका 86,000 करोड़ रुपए का आयात हुआ था। यह पिछले साल हुए 30 लाख करोड़ के कुल आयात का 2.8% है।

14 सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि रुपए में गिरावट रोकने के लिए गैर-जरूरी वस्तुओं का आयात कम करने के उपाय होंगे। पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि निर्यात बढ़ाने से ही स्थिति मजबूत होगी।

कुल आयात का 2.8%: जिन वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा, पिछले साल उनका 86,000 करोड़ का आयात हुआ

वस्तु	पुरानी ड्यूटी	नई ड्यूटी
एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन	10%	20%
एसी-फ्रिज के कंप्रेशर	7.5%	10%
जूते-चप्पल	20%	25%
स्पीकर, रेडियल टायर	10%	15%
डायमंड, लैब में बने डायमंड, पॉलिश्ड रत्न	5%	7.5%
सोना, चांदी, प्लैटिनम की ज्वैलरी	15%	20%
प्लास्टिक के शावर, सिंक, वाश बेसिन	10%	15%
प्लास्टिक बॉक्स, कंटेनर, बोतल	10%	15%
प्लास्टिक फर्नीचर फिटिंग्स, सजावटी शीट	10%	15%
ट्रंक, सूटकेस, ब्रीफ केस, ट्रैवल बैग	10%	15%
विमान ईंधन	0%	5%

फैसले से घरेलू इंडस्ट्री को फायदा होगा

जिन वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है, उनकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होती है। इंपोर्टेड चीजें महंगी होने से इन्हें बनाने वाली घरेलू कंपनियों को फायदा मिलेगा।

एक्सपोर्टर्स को ज्वैलरी का निर्यात घटने का अंदेशा

जेम्स-ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मनीष जैन ने बताया कि घरेलू ज्वैलरी इंडस्ट्री में डायमंड और रत्नों की हिस्सेदारी 5-10% ही है। इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जेम्स-ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के उपाध्यक्ष कोलिन शाह ने कहा कि आयात शुल्क बढ़ने से ज्वैलरी निर्यात गिर सकता है।

आयात कम होने से चालू खाते के घाटे में कमी आएगी

आयात शुल्क बढ़ाकर सरकार चालू खाते का घाटा कम करना चाहती है। देश में विदेशी मुद्रा आने और यहां से बाहर जाने के अंतर को चालू खाते का घाटा कहा जाता है। 2017-18 में यह जीडीपी का 1.9% था। लेकिन इस साल इसके 2.8% तक पहुंचने का अंदेशा है। पहली तिमाही में यह 2.4% था।

क्रूड 4 साल में सबसे महंगा, इससे आयात बिल बढ़ा है

क्रूड के दाम 4 साल की ऊंचाई पर पहुंचने और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट से आयात बिल बढ़ रहा है। अप्रैल से अगस्त के दौरान कच्चे तेल का आयात सिर्फ 6.5% बढ़ा, लेकिन इसके आयात पर खर्च 67% बढ़ा है।

रुपया 13% कमजोर, इससे भी आयात बिल में बढ़ोतरी

रुपया इस साल 13% कमजोर हो चुका है। अगस्त से इसमें 6% गिरावट आई है। 12 सितंबर को यह 72.99 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। बुधवार की ट्रेडिंग में एक डॉलर 72.60 रुपए पर बंद हुआ।